भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2684
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के तहत तमिलनाडु के लिए निधि

†2684. **सुश्री एस. जोतिमणि:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा योजना और पीएम श्री स्कूलों सहित विभिन्न केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु को आवंटित कुल धनराशि का वर्षवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या तमिलनाडु के स्कूल और उच्च शिक्षा क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में निधि आवंटन में कोई कमी/वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) राज्य में सरकारी विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के उन्नयन के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितने संस्थान लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु राज्य को आवंटित कुल निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

योजना	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
समग्र शिक्षा	3055.41	3444.71	3535.25
उल्लास	7.19*	9.83	8.28
पीएम पोषण	716.34	696.89	760.34

**वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 हेतु आवंटित कुल राशि*

तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ख): भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। समग्र शिक्षा को एनईपी 2020 के साथ संरेखित किया गया है। स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में पहुंच, समता, गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निधि आवंटन किया जाता है।

वित्त पोषण में वृद्धि या कमी जैसे कोई भी संशोधन, शैक्षिक प्राथमिकताओं, कार्यान्वयन प्रगति और राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से किए जाते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय राज्य सरकार के परामर्श से लिए जाते हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और पहलों के माध्यम से तमिलनाडु के शिक्षा क्षेत्र को निरंतर सहायता प्रदान कर रहीं है, जिसका उद्देश्य अधिगम परिणामों में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, अवसंरचना विकास आदि है।

(ग): समग्र शिक्षा योजना सरकारी स्कूलों के अवसंरचना निर्माण और स्तरोंन्नयन में सहायता करती है। इस संबंध में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं तथा प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडबल्यूपी एंड बी) तैयार किया जाता है। इन योजनाओं का मूल्यांकन/अनुमोदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

समग्र शिक्षा (2018-19) की शुरुआत से, राज्य सरकार के प्रस्तावों और योजनाओं के मौजूदा मानदंडों के आधार पर तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों के स्तरोंन्नयन सहित 96978 अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए कुल 1200.95 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)/पीएम-उषा, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और समानता में सुधार करने के लिए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के सहयोग से वित्त पोषण और नीतिगत सहायता प्रदान करके राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करना है। वर्ष 2013 में इस योजना की शुरूआत के बाद से, तमिलनाडु राज्य में 526 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ कुल 99 इकाइयों को विभिन्न घटकों के तहत मंजूरी दी गई है, जिनमें मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्नयन, विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान और महाविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान आदि शामिल हैं।

******